

प्रेषक,

सौरभ जैन,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

शहरी विकास विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-२

देहरादून: दिनांक-५ मार्च, 2008

विषय : नगर पंचायत मुनि की रेती के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष-2005-06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० 1721/V-श०वि०-०५-५५६(सा०)/०४ दिनांक 14-9-05 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत, मुनि की रेती के अन्तर्गत अवस्थापना विकास सम्बन्धी तीन कार्यों हेतु रू० 71.26 लाख की धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा शासनादेश संख्या 801/V-श०वि०-०६- 66(सा०)/०३ टी०सी० दिनांक 29 मार्च, 2006 के द्वारा रू० 53.45 की धनराशि अवमुक्त की गई थी। अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मुनिकी रेती के पत्र दिनांक 8-1-2008 के माध्यम से उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य (क्रमांक-1 सामुदायिक भवन का निर्माण रू० 15.21 लाख) के दूसरे भाग (पार्ट-2) शासनादेश संख्या 644 दिनांक 17-7-2006 द्वारा रू० 81.45 लाख स्वीकृत होने के कारण दोनों कार्य एकीकृत रूप से कराया जाना अवगत कराया गया है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 14-9-2005 द्वारा स्वीकृत कार्य को शासनादेश दिनांक 13-7-2006 द्वारा स्वीकृत कार्य भाग-2 होने के कारण, इस कार्य (प्रथम भाग रू० 15.21 लाख) को भी शासनादेश दिनांक 13-7-2006 की प्रशासकीय स्वीकृति में ही सम्मिलित करते हुए अवशेष दो कार्यों के लिए स्वीकृत 56.05 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय प्रदान करते हुए अवमुक्त धनराशि रू० 53.45 के उपयोग के उपरान्त दो कार्यों के लिए प्राप्त न्यूनतम निविदा के आधार हुई बचत के उपरान्त स्वीकृति हेतु अब अवशेष रू०-2.50 लाख (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि रू०-2.50 लाख (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. इस शासनादेश के माध्यम से शासनादेश सं० 1721/V-श०वि०-०५-५५६(सा०)/०४ दिनांक 14-9-05 द्वारा स्वीकृत दो कार्यों (कैलाश गेट के पास घाट निर्माण रू० 28.37 लाख तथा नगर पंचायत कार्यालय के पीछे घाट निर्माण रू० 27.68 लाख) हेतु अर्थात् कुल 56.05 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
3. शासनादेश संख्या 644/V-श०वि०-०६-36(सा०)/०६ दिनांक 13-7-2006 की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति पृथक से निर्गत की जा रही है।
4. शासनादेश सं० 467/V-श०वि०-०६-306 (सा०)/०५ दिनांक 6-3-06 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
6. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

क्रमशः

7. स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
 8. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
 9. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
 10. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनोद्देश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
 11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2008 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- 2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 02/XXVII(2)/2008, दिनांक- 27 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।

सं0-222(1)/IV-शा0वि0-08, तददिनांक। ५/3

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, टिहरी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. प्रशासक/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मुनि की रेती।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।